

प्रेषक,

अनूप वधावन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक: 09 जून, 2008
विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु वचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 145/रा.नि.आ./2006 दिनांक 11.4.2008 एवं शासनादेश संख्या 332/XII/2008/82(26)/2003, दिनांक 09 अप्रैल 2008 तथा शासनादेश संख्या 424/XII/2008/82(26)/2003, दिनांक 27 मई 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुसार पूर्व में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के नये भवन हेतु कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय हेतु रु0 20,00,000/- (रु0 बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-267/xxvii/(1)/08 दिनांक 27-3-2008 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-177/xxxvii (7)/2008 दिनांक 01-5-2008 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर कर व्यय की कार्यवाही की जाय।

4. व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक तक ही रखा जाय। उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फांट अपने स्तर से किया जाय।

5. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सरणी बनाकर ही किया जाय।

6. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी हान वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

7. व्यय करने से पूर्व बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है। उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. निर्माण कार्य एवं सामग्री कय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय।
9. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-06 -राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकाय आदि हेतु) की मानक मद-12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के कय के नामें डाला जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(अनूप बघावन)
सचिव

संख्या 417 /XII/08/82(08)/2007 तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- ✓ 6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय क अवलोकनार्थ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एम0सी0संप्रती)
अपर सचिव